साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 10, अंक : 48 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 2 जुलाई 2025 से 8 जुलाई 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से क्या हुआ हासिल, सीएसई का आकलन

नई दिल्ली(एजेंसी) संघर्षों, व्यापार युद्धों और जलवायु प्रभावों से जूझ रही दुनिया की छाया 16 जून से 26 जून 2025 के दौरान जर्मनी के बॉन शहर संपन्न संयुक्त राष्ट्र के मध्यवर्षीय जलवायु वार्ताओं (क्लाइमेट टॉक्स) पर स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

बातचीत की शुरुआत ही मुश्किल माहौल में हुई, जब विकासशील देशों को जलवायु वित्तीय दायित्वों और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों के एकतरफा व्यापार उपायों, जैसे कार्बन सीमा कर (बॉर्डर टैक्स) के प्रभावों पर चर्चा के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्हें विकसित देशों के विरोध का सामना करना पड़ा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने इन वार्ताओं के निष्कर्षों का मूल्यांकन किया और पाया कि बॉन की यह बैठक भी चिर-परिचित टकरावों और कई मुद्दों पर धीमी प्रगति की शिकार हो गई।

सीएसई की एक टीम ने इस सम्मेलन में भाग लिया और इसकी रिपोर्टिंग की। बॉन से बोलते हुए सीएसई की क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम मैनेजर अवंतिका गोस्वामी ने कहा- हम विकसित देशों की ओर से बहुपक्षीयता (मल्टीलेटरलिज्म) को निभाने की कोई गंभीर इच्छा नहीं देख रहे हैं, और बॉन की बैठक ने इसे स्पष्ट कर दिया। अनुच्छेद 9.1 पर गहराई से चर्चा करने से इनकार किया गया और विकासशील देशों द्वारा उठाए गए एकतरफा व्यापार उपायों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया, जो इस क्षेत्र में मौजूद शक्ति के असंतुलन का प्रतीक है। हालांकि जस्ट ट्रांजिशन जैसे मुद्दों पर सिविल सोसायटी लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन बाकी सभी मंच इस वजह से ठप हैं, क्योंकि अमीर देशों (ग्लोबल नॉर्थ) ने अब भी अपने ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के अनुसार बाकी दुनिया को जलवायु कार्रवाई के लिए जरूरी मदद, फंडिंग और समर्थन देने से इनकार कर रखा है। यूएई जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम (जेटीडब्ल्यूपी) के तहत विकासशील देशों ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एकतरफा व्यापारिक नीतियों, जैसे यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (सीबीएएम) जैसी व्यापार-प्रतिबंधक नीतियों के प्रभावों को प्राथमिकता से उठाया। वहीं, विकसित देशों ने जस्ट ट्रांजिशन के रास्तों को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुरूप ढालने और उन्हें उन राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में शामिल करने पर ज़ोर दिया जिन्हें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (एयूएनएफसीसीसी) को सौंपा जाता है। बॉन में एक मसौदा वार्तापत्र (ड्राफ्ट नेगोशिएटिंग टेक्स्ट) तैयार किया गया, जिसमें जस्ट ट्रांजिशन के लिए संपूर्ण-अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण अपनाने, सभी के लिए स्वच्छ, भरोसेमंद, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने, तथा ऊर्जा संक्रमण के लिए विविध रास्तों को मान्यता देने पर ज़ोर दिया गया। इस मसौदे में कुछ क्षेत्रों में सहमति बनी, जिनमें सिविल सोसायटी द्वारा रखे गए कई प्रस्ताव भी शामिल हैं। यह मसौदा अब बेलेम (ब्राज़ील) में होने वाले कॉप30 में औपचारिक वार्ताओं के लिए भेजा जाएगा।

ग्लोबल साउथ पर बोझ बढ़ाते हैं एकतरफा व्यापारिक उपाय 'समान विचार वाले देशों (एलएमडीसी) द्वारा शुरू में एक स्वतंत्र एजेंडा आइटम के रूप में प्रस्तावित किए गए एकतरफा व्यापारिक उपाय (यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स-यूटीएम) अंततः जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम और रिस्पॉन्स मेजर्स फोरम के तहत चर्चा के विषय बने। विकासशील देशों ने इन व्यापार-प्रतिबंधक उपायों के उन नकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया, जो आर्थिक असमानता को बढ़ावा देते हैं और ग्लोबल साउथ पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। जेडीडब्ल्यूपी में देशों ने इन प्रभावों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समर्थन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जिसमें चीन ने विश्व व्यापार संगठन के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। वहीं, रिस्पॉन्स मेजर्स ट्रैक में जी-77 और चीन ने कातोविचे समिति के कार्यों में यूटीएम को प्राथमिकता देने की मांग की, लेकिन यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देशों ने इसका विरोध किया और सुझाव दिया कि यह विषय व्यापार-विशेष मंचों में सुलझाया जाना चाहिए।

ग्लोबल स्टॉकटेक पर चर्चा जानबूझकर अटकाई गई ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) के क्रियान्वयन पर यूएई डायलॉग को लेकर हुए अनौपचारिक विचार-विमर्श बिना किसी आम सहमति के समाप्त हो गए। विकसित देशों ने जीएसटी के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए हर वर्ष एक समेकित (सिंथेसिस) रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव रखा, जबकि विकासशील देशों ने ज़ोर दिया कि प्राथमिकता राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को लागू करने पर होनी चाहिए, न कि इस संवाद को एक रिपोर्टिंग तंत्र में बदलने पर। विकासशील देशों ने यह भी मांग की कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का हवाला दिया जाए, ताकि इस डायलॉग के उद्देश्य और दायरे को स्पष्ट किया जा सके।

अनुकूलन पर बातचीत रुकी ग्लोबल गोल ऑन अडैप्टेशन (जीजीए) पर बातचीत मुख्य रूप से इस बात पर अटक गई कि विकासशील देशों द्वारा जलवायु प्रभावों के अनुरूप ढलने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, उनकी प्रगति को मापने के लिए कौन से सूचकांक (इंडिकेटर्स) अपनाए जाएं। दुबई में कॉप28 के दौरान तय हुए जीजीए ढांचे के तहत विभिन्न लक्ष्यों पर प्रगति मापने के लिए संकेतक विकसित किए जाने हैं। माध्यमों की उपलब्धता में मुख्य रूप से वित्त शामिल है, लेकिन इसमें प्रौद्योगिकी और क्षमतावर्धन जैसे घटक भी आते हैं। विकासशील देश चाहते हैं कि इन संसाधनों की उपलब्धता को मापने के स्पष्ट और न्यायसंगत मानदंड तय किए जाएं, जबकि इस पर सहमति नहीं बन सकी है।

जीजीए वार्ता में अन्य विवादास्पद मुद्दे भी बने गतिरोध का कारण ग्लोबल गोल ऑन अडैप्टेशन (जीजीए) के मसौदे में कई अन्य विवादास्पद मुद्दे भी सामने आए, जिनमें परिवर्तनकारी अनुकूलन) से जुड़ी भाषा, हर दो साल में जारी होने वालीपारदर्शिता रिपोर्ट्स और अनुच्छेद 9 शामिल हैं। इन मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन सकी और चर्चा में गतिरोध बना रहा। बॉन में तैयार किए गए एक अनौपचारिक नोट के आधार पर अब इन वार्ताओं को कॉप30 (बेलेम, ब्राज़ील) में आगे बढ़ाया जाएगा।

राज्य सरकार खिवनी अभयारण्य के प्रभावितों के साथ है –मुख्यमंत्री डॉ. यादव

दोषी अधिकारियों- कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इछावर-खातेगांव क्षेत्र के प्रभावितों के साथ की भेंट

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खिवनी अभयारण्य के लिए वन विभाग द्वारा खातेगांव इछावर क्षेत्र मे की गई कार्यवाही से प्रभावित क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ समत्व भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवेदनशीलता से शिकायतों और पीड़ा को सुना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्रवाई पर खेद व्यक्त करते हुए, स्थिति का उचित समाधान निकालने, शिकायतों की जांच करवाने, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्यवाही करने और क्षेत्र के लोगों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावितों के साथ है। यह सुनिश्चित किया जाएगा की बरसात में किसी को कोई तकलीफ ना हो। राहत के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जांएगी।

जल प्रदाय योजना का केंद्रीय अधिकारियों ने किया निरीक्षण

बड़वानी जल जीवन मिशन के तहत सेगवाल-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का निरीक्षण केंद्रीय नोडल अधिकारी पार्थ सारथी गुराला (संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय) एवं तकनीकी अधिकारी देवेंद्र सिंह बाजवा ने किया।

इंदौर से स्थानांतरित हुए संयुक्त संचालक डॉ. आर.आर. पटेल को दी गई भावभीनी विदाई

मीडिया संगठनों व प्रशासनिक अधिकारियों ने सराहा योगदान

इंदौर (नगर प्रतिनिधि) संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, इंदौर में पदस्थ संयुक्त संचालक डॉ. आर.आर. पटेल को भोपाल स्थानांतरित होने पर सोमवार को एक गरिमामय समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही इंदौर के मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों ने डॉ. पटेल के कार्यों की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम में जिला पंचायत इंदौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी, मध्यप्रदेश स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री प्रवीण खारीवाल, वूमन्स प्रेस क्लब की अध्यक्ष श्रीमती शीतल राय सहित विभिन्न पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने डॉ. पटेल के प्रशासन और प्रेस के बीच सेतु के रूप में निभाई गई भूमिका को अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव सहित अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर उन्होंने कुशल समन्वय और दक्ष प्रबंधन से विभागीय कार्यों को उत्कृष्ट रूप से निभाया। डॉ. पटेल की कर्मठता, लगनशीलता और सकारात्मक सोच प्रशंसनीय रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. पटेल राज्य स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को उसी दक्षता से निभाएंगे जैसे इंदौर में निभाया। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी ने कहा कि डॉ. पटेल एक विलक्षण अधिकारी हैं, जिन्होंने मीडिया और प्रशासन के बीच सशक्त समन्वय स्थापित कर इंदौर को नई पहचान दी। वे सदैव सहजता, संवेदनशीलता और कुशल संवाद के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। वरिष्ठ पत्रकार श्री कीर्ति राणा ने भी अपने अनुभव साझा किया। समारोह में विभिन्न वक्ताओं ने डॉ. पटेल के प्रशासनिक योगदान, मीडिया से उनके सौहार्दपूर्ण संबंधों और जनसंपर्क क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की। उपस्थित जनों ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर शुभकामनाएं दीं। डॉ. आर.आर. पटेल ने सभी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इंदौर में कार्यकाल उनके लिए अत्यंत प्रेरक और सीख से भरपूर रहा। उन्होंने मीडिया और प्रशासन के बीच सहयोग की भावना को हमेशा प्राथमिकता दी और विश्वास जताया कि यह परंपरा आगे भी बनी रहेगी। समारोह में मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों और मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों आदि ने भी डॉ. पटेल को शाल, श्रीफल, दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।

जल संरक्षण का जन आंदोलन बना जल गंगा संवर्धन अभियान –डॉ. मोहन यादव

क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंचतत्व से बना शरीरा रामचरित मानस की इस चौपाई के पंचतत्वों में से एक जल, जीवन का आधार है। हमें जीवन के अस्तित्व के लिये जल को संरक्षित करना ही होगा। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना जरूरी है। ऋग्वेद की ऋचाओं में जल के महत्व, विशेषताओं और संरक्षण का संकेत है। रामायण और महाभारत में प्रकृति के संरक्षण का उल्लेख है। जल संरक्षण हमारी पुरातन संस्कृति है। यह अपनी परंपरा और संस्कारों की ऐतिहासिक विरासत है, जिसे हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विरासत से विकास की दृष्टि समग्र कल्याण के लिए है, जो प्रकृति संवर्धन से लेकर विकास के हर पक्ष में समाहित है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लंबे समय तक जल संरक्षण का अभियान चलाया था उन्हीं से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश में हमने जल गंगा संवर्धन अभियान की संकल्पना की। इस अभियान का शुभारंभ 30 मार्च गुड़ी पड़वा, नववर्ष विक्रम संवत अवसर पर महाकाल की नगरी उज्जयिनी के शिप्रा तट से किया गया। यह अभियान जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जन-जागरुकता को समर्पित रहा है। जल संग्रह के कई कीर्तिमान रचने के साथ आज हम जल संरक्षण की समृद्धि का उत्सव मना रहे हैं।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस 90 दिन तक चले अभियान में पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जल-संरचनाओं पर काम हुआ है। अभियान में खंडवा जिले ने 1.29 लाख संरचनाओं का निर्माण किया है। इस विशेष उपलब्धि के लिए खंडवा को भू-गर्भ जल भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल सुरक्षा और प्रभावी जल प्रबंधन के लिए कैच द रेन अभियान शुरू किया। इसी से प्रेरणा से लेकर मध्यप्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वर्षा की एक-एक बूंद को सहेजने का प्रयास किया गया। प्रदेश में पहली बार वर्षा जल को सहेजने का बड़े स्तर पर अभियान चला इससे भविष्य में भू-जल की निर्भरता कम होगी और पानी की हर बूंद का उपयोग होगा।

हमने प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ मंत्र को आत्मसात किया और अपनी जीवन शैली में बदलाव कर पर्यावरण रक्षा का सूत्र हाथ में लिया है। इससे जन-जन में पर्यावरण मित्र के रूप में जीवन जीने की परंपरा निर्मित हुई है। प्रदेशवासी मिशन लाइफ के अनुसार प्रकृति के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में पहली बार री-यूज वाटर पोर्टल निर्मित किया जा रहा है। यह पहल प्रदेश में जल संरक्षण और पुनः उपयोग की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह प्रदेश जल प्रबंधन के लिए तीन सिद्धांत री-यूज, रीड्यूज और री-साइकल पर आधारित रणनीति बनाकर काम कर रहा है।

यह हमारा सौभाग्य है कि मध्यप्रदेश की धरती प्रकृति की विपुल सम्पदा से समृद्ध है। यह मां नर्मदा, शिप्रा मईया, ताप्ती और बेतवा सहित लगभग 267 नदियों का मायका है। प्रदेश में पहली बार नदियों को निर्मल और अविरल बनाने के लिए 145 से अधिक नदियों के उद्गम को चिन्हित किया गया और साफ-सफाई के साथ पौधरोपण की शुरुआत हुई है। नदियों के तट पर पौधरोपण की यह पहलनदियों को उनके मायके में हरि चुनरी ओढ़ाने का प्रयास है। प्रदेश में पहली बार जल सरंक्षण के साथ जल समृद्धि की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की पहल की गई। इसके तहत राजाभोज ने बसाये भोपाल की ऐतिहासिक धरोहर बड़े बाग की बावड़ी को सहेजने और पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस अभियान के अंतर्गत हमने 200 वर्ष पहले लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाई गई होलकर कालीन बावड़ी को जीर्णोद्धार उपरांत नया स्वरूप प्रदान किया है। इस बावड़ी का लोकर्पण करते हुए मुझे यह महसूस हुआ कि हम माता अहिल्या के लोक कल्याण के युग में पहुंच गये हैं। बावड़ियां हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर हैं, इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिये प्रदेश भर में दो हजार से अधिक बावड़ियों को पुनर्जीवित करते हुए बावड़ी उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने हमारी युवा शक्ति को जल सैनिक बनाने का आह्वान किया था। इस अभियान में, मध्यप्रदेश में पहली बार 2 लाख 30 हजार जल दूत बनाये गये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पानी बचाने के लिए यह अमृत मित्र भविष्य में जल सुरक्षा के अग्रदूत बनेंगे। प्रदेश में पहली बार डेढ़ लाख से अधिक कृषकों ने सभी विकासखंडों में 812 पानी चौपाल का आयोजन किया। इसमें किसानों ने अपने गांव के खेतों, जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार पर विचार-विमर्श किया।

प्रदेश में पहली बार खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रोकने के लिए खेत तालाबों का चयन सिपरी सॉफ्टवेयर से किया गया। अभियान में 83 हजार से अधिक बनने वाले खेत-तालाबों से प्रदेश के अन्नदाता में नई उम्मीद जागी है। अब वे अपने खेत में एक नहीं कई फसलें ले सकते हैं। खेत तालाब के अलावा अमृत सरोवर और डगवेल रिचार्ज बनाने में भी सिपरी सॉफ्टवेयर, एआई और प्लानर सॉफ्टवेयर जैसी तकनीक का उपयोग किया गया है। इस तकनीक से निर्धारित लक्ष्य को समय रहते प्राप्त करने में आसानी हुई है और गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए डेशबोर्ड डाटा को एआई के माध्यम के उपयोग से अभियान की प्रगति में सुधार और गति दी गई।

इस अभियान में प्रदेश के नगर-नगर और गांव-गांव में जल स्रोतों को शुद्ध और उपयोगी बनाने का कार्य चला, अनेक पोखर और बावड़ियों को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। यह सरकार और समाज का संयुक्त प्रयास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पानी की बूंद-बूंद सहेजने का जो प्रयत्न किया गया है वह हमारे किसान भाइयों के लिए पारस पत्थर का काम करेगा। सूखे खेत हरे-भरे होंगे, सुनहरी फसलें लहलहायेंगी। हमारा किसान समृद्ध होगा और मध्यप्रदेश की धरती समृद्ध होगी। वर्षा के जल को संग्रहित करने और पुराने जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए चलाए गए अभियान की सफलता का सबसे बड़ा आधार रहा जनभागीदारी। सरकार, शासन-प्रशासन, समाजसेवी और प्रदेश के आमजन ने इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद अब पौधरोपण का व्यापक अभियान चलाया जायेगा। मुझे खुशी है कि जल गंगा संवर्धन अभियान शासन के साथ जनता के लिए, जनता का अभियान बन गया है। इस अभियान ने जनआंदोलन का स्वरूप ले लिया है। प्रदेश ने यह प्रमाणित किया है कि यदि सरकार और जनता मिलकर कार्य करेंतो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। किसान, महिला, युवा और विद्यार्थियों ने जल संरक्षण को जीवन का मंत्र बना लिया है। इससे समाज में जल संरक्षण का भाव और भागीदारी का मानस विकसित हुआ है। इस अभियान ने हम सभी के मन को एक नये संकल्प और ऊर्जा से भर दिया है। यह अभियान केवल जल संरक्षण का कार्य नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भविष्य की सुरक्षा का वह सूत्र है, जिससे प्रदेश की समृद्धि जुड़ी है।

अद्भिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च।

महाभारत के शांति पर्व का यह श्लोक जल के महत्व और जीवन में इसकी भूमिका को दर्शाता है। मैं प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता से पानी की बूंद-बूंद बचाने और जल समृद्ध राज्य बनाने का आह्वान करता हूं। आईये, हम सब मिलकर पानी की हर बूंद बचाने का संकल्प लें, जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ायें। मुझे उम्मीद है कि जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश में जल की प्रचुर उपलब्धता और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी।

(लेखक, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

सूरत में सफल रहा निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रदेश को मिले 15,710 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव

निवेश प्रस्तावों के जरिए 11,250 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रविवार को सूरत (गुजरात) में यहां के निवेशकों के साथ हुआ संवाद सत्र (इंटरैक्टिव सेशन) पूर्णतः सफल रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सूरत में हुए इस आयोजन से मध्यप्रदेश को 15,710 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में 11,250 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया %एक्स% पर कहा कि मध्यप्रदेश अपार संभावनाओं की भूमि है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को गति को तेज करने और गुजरात राज्य के निवेशकों को उनके ही निकट सुविधा देने के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का एक कार्यालय अहमदाबाद में भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रविवार को उद्योग नगरी सूरत में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में सभी उद्यमी बंधुओं के साथ विस्तार से संवाद कर उन्हें मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों एवं निवेशकों के साथ प्रदेश में निवेश के संबंध में वन-टू-वन चर्चा भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुजरात राज्य के निवेशकों की प्रगतिशीलता एवं उद्यमशीलता की सराहना करते हुए कहा कि देश के विकास में गुजरात का अमूल्य योगदान है।

घरों में निकल रहा लार्वा

इंदौर (नगर प्रतिनिधि) जून माह में डेंगू- मलेरिया के मरीज तेजी से बढ़े हैं। जून में 12 मरीज डेंगू प्रभावित व 3 मलेरिया प्रभावित मरीज मिले हैं, जिसे लेकर विभाग की चिंता भी बढ़ी है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. रश्मि शर्मा दुबे ने बताया, अलग-अलग टीम बनाकर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा दवा छिड़काव भी कराया जा रहा है। नगर निगम के सहयोग से फॉगिंग भी कराई जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बालाघाट जिले की सूमा उइके की पहल को सराहा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में बालाघाट जिले के कटंगी ब्लॉक की सूमा उइके का उल्लेख करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार, महिलाओं- युवाओं -गरीबों और किसानों के जीवन में बदलाव लाने और उन्हें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में समर्पित भाव से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में राज्य के इन प्रयासों का उल्लेख करने से प्रदेशवासियों का उत्साह बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले के कटंगी विकासखंड के ग्राम भजियापार की सूमा उइके ने स्व सहायता समूह से जुड़कर मशरूम की खेती और पशुपालन की ट्रेनिंग ली और आय बढ़ने पर थर्मल थेरेपी और दीदी केंटीन से आय अर्जित कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयनगर लालघाटी क्षेत्र में श्री रमेश विजयवर्गीय के निवास पर श्रवण किया।

बालाघाट जिले की सूमा उइके की पहल को सराहा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में बालाघाट जिले के कटंगी ब्लॉक की सूमा उइके का उल्लेख करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार, महिलाओं- युवाओं -गरीबों और किसानों के जीवन में बदलाव लाने और उन्हें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में समर्पित भाव से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में राज्य के इन प्रयासों का उल्लेख करने से प्रदेशवासियों का उत्साह बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले के कटंगी विकासखंड के ग्राम भजियापार की सूमा उइके ने स्व सहायता समूह से जुड़कर मशरूम की खेती और पशुपालन की ट्रेनिंग ली और आय बढ़ने पर थर्मल थेरेपी और दीदी केंटीन से आय अर्जित कर रही हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008